भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2058

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

2058. **डॉ. के. सुधाकरः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग (एसएससी) को बढ़ावा देने और देश को राष्ट्रों के समूह में ग्लोबल साउथ की आवाज बनाने के लिए कदम उठा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की विश्व भर में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना है और यदि हां, तो प्रस्तावित वाणिज्य दूतावासों और मिशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारा और अन्य परिवहन गलियारों की प्रगति के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्व के देशों के बीच बढ़ते संघर्षों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व भर में भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) भारत हमेशा से ही विकासशील देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों के समग्र मानव-केंद्रित विकास के लिए रचनात्मक रूप से प्रयास करता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने

ग्लोबल साउथ के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई विकास साझेदारी पहल की हैं, जिसमें कनेक्टिविटी और आर्थिक अंतर-संबंध बढ़ाने के लिए अवसंरचना परियोजनाएं शुरू करना, साथ ही वित्तीय, बजटीय और मानवीय सहायता प्रदान करना और छात्रों एवं पेशेवरों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके क्षमता निर्माण और कौशल विकास में योगदान देना शामिल है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप कि भारत की जी-20 अध्यक्षता को ग्लोबल साउथ में सहभागी देशों के परामर्श से आकार दिया जाए, भारत ने जनवरी 2023, नवंबर 2023 और अगस्त 2024 में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) के तीन संस्करणों का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन के प्रत्येक संस्करण में राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों, मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर 100 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार सहित हमारी साझा विकास प्राथमिकताओं और चिंताओं पर ग्लोबल साउथ के देशों के नेताओं के साथ विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक उपयोगी मंच प्रदान किया।

09-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना और जी-20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा को जी-20 सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया जाना यह दर्शाता है कि ग्लोबल साउथ के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण और समर्थन का विकासशील और विकसित देशों पर काफी प्रभाव पड़ता है।

(ख) वर्तमान में फुकुओका (जापान), कज़ान (रूस) और येकेत्रिनबर्ग (रूस) में कोंसलावासों को कार्यशील करने के प्रयास चल रहे हैं। भावी योजनाओं में यूरोप और लातिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्रों में 5 नए राजनयिक मिशन खोलना शामिल है।

(ग) जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के नेताओं ने एक नए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की। इसमें दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें डिजिटल, ऊर्जा और रेलवे कनेक्टिविटी शामिल होगी और यह मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप

में एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा पार जहाज-से-रेल पारगमन नेटवर्क प्रदान करेगा, जिससे इन क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार संभव हो सकेगा।

इस गलियारे का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के विकास और निर्यात को सुगम बनाना; बिजली की विश्वसनीय सुलभता का विस्तार करने के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाना और ऊर्जा ग्रिड एवं दूरसंचार लाइनों को जोड़ना; उन्नत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के नवाचार को सक्षम बनाना; और डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, व्यापार सुलभता को बढ़ाना, आर्थिक एकता को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है - जिसके परिणामस्वरूप एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का परिवर्तनकारी एकीकरण होगा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के संचालन के लिए सहयोग से संबंधित एक अंतर-सरकारी रूपरेखा करार (आईजीएफए) पर 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस रूपरेखा के मुख्य तत्वों में एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सहित एक संभारतंत्रीय मंच का विकास एवं प्रबंधन, और आईएमईसी को सक्षम करने के लिए सभी प्रकार के सामान्य कार्गो, बल्क, कंटेनर और तरल बल्क को संभालने के लिए आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं का प्रावधान शामिल है। यह आईएमईसी पहल के तहत पहला करार है। आईएमईसी गलियारा, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का आर्थिक एकीकरण है, में कई हितधारक शामिल हैं और यह प्रारंभिक चरण में है।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) 7,200 किलोमीटर लंबा बहुविध परिवहन मार्ग है जिसे ईरान के माध्यम से हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, जो रूस तक फैला हुआ है। वर्तमान में आईएनएसटीसी के माध्यम से माल की आवाजाही में कुछ अवसंरचनात्मक और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अनुपस्थित अवसंरचना को विकसित करने के लिए काम जारी है।

(घ) वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में, भारत दुनिया में बढ़ते संघर्षों के प्रति चिंतित रहा है, जो मानवीय संकटों के साथ-साथ खाद्य, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सभी वैश्विक संघर्षों में, भारत ने हमेशा हिंसा और शत्रुता को रोकने, नागरिकों को मानवीय सहायता देने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए राजनय और बातचीत का रास्ता अपनाने का समर्थन किया है। भारत ने विभिन्न वैश्विक

संघर्षों में शामिल सभी पक्षकारों और हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क बना रखा है। उच्चतम स्तर पर वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के साथ इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है।

(ङ) सरकार ने विदेशों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) विदेशों में अपने सांस्कृतिक केंद्रों और मिशनों/केंद्रों के माध्यम से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ योग, नृत्य, संगीत (गायन और वाद्य), संस्कृत और हिंदी की शिक्षा देना; भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करना/उन्हें सहयोग प्रदान करना; विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन पीठों को सहयोग देना; महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय महापुरुषों की प्रतिमाओं/मूर्तियों को उपहार स्वरूप देना, दृश्य कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आयुर्वेद दिवस और भारतीय उत्सवों का आयोजन, भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना, विभिन्न आगंतुक कार्यक्रमों (शैक्षणिक/प्रतिष्ठित/महत्वपूर्ण/जेन. नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क) के तहत आगंतुकों की मेजबानी करना; और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित करना शामिल है।

सरकार ने हाल के दिनों में विदेशों में, खासकर दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए सचेत प्रयास किए हैं। मार्च 2020 में, ऐसी संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विदेश मंत्रालय में एक समर्पित प्रभाग - विकास भागीदारी प्रशासन (डीपीए)- IV की स्थापना की गई थी। यह प्रभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है। वर्तमान में, विदेश मंत्रालय, डीपीए - IV प्रभाग के माध्यम से, 4 विश्व धरोहर स्थलों पर संरक्षण परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें ता प्रोहम मंदिर, कंबोडिया; प्रीह विहियर मंदिर, कंबोडिया; वट फो मंदिर, लाओ पीडीआर; माई सन मंदिर समूह, वियतनाम शामिल हैं।

*****